युवा सहकार

www.nycsindia.com

जनवरी 2025, नई दिल्ली

युवाओं को रोजगार

लीक से हटकर अवसर बनाने की कोशिश

अंदर के पन्नों पर:

- 10 हजार नए एम-पैक्स का शुभारंभ
- पुणे पुस्तक महोत्सव में बने पांच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

Did You Know?

2025 is the International Year of Cooperatives!

The UN declared 2025 as a year to celebrate cooperatives around the world. Cooperatives are businesses owned by their members, focusing on both profit and the needs of their communities. They play a big role in sustainable development and achieving the UN's Sustainable Development Goals by 2030.

There will be a year-long celebration to raise awareness about cooperatives and their positive impact.

युवा सहकार

वर्ष : 01, अंक-07, जनवरी-2025

निदेशक मंडल एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशन प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं पारस ऑफसेट प्रा. लि. कुंडली, हरियाणा द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमार: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

रोजगार का बदलता तरीका 04
'इरमा' बनेगा देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय 05

06 युवाओं को रोजगार: लीक से हटकर अवसर बनाने की कोशिश

11 एनवाईसीएस के सीईओ बने डॉ. रामचंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी

सहकारिता लिखेगी नई इबारत 12
ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देंगे पैक्स 14
दाम स्थिर रखने को महाराष्ट्र पर घटानी होगी प्याज की निर्भरता 16
कैंपस कोऑपरेटिव: विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद 22
गृहिणी जो बनी केक कारोबारी 24
जैविक खेती से बढ़ेगा रोजगार 26
नौकरी छोड़ जैविक खेती को दे रहे बढ़ावा 28
कोऑपरेटिव बैंकों की बदलेगी बैलेंस शीट 30

रोजगार का बदलता तरीका

रोजगार को लेकर मौजूदा सरकार हमेशा से विरोधियों के निशाने पर रही है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने इसका प्रयास नहीं किया। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को पीएलआई स्कीम जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया गया लेकिन ये योजनाएं रोजगार के मोर्चे पर अपेक्षित नतीजे नहीं दे पाई।

भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक देश की ज्यादातर युवा आबादी को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होंगे। हालांकि, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में सरकार के लिए सबको नौकरी देना संभव नहीं है। इसलिए सरकार रोजगार सृजन के पारंपरिक तौर-तरीकों की बजाय ऐसे गैर-परंपरागत विकल्पों में अवसर तलाश रही है जिनसे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के दायरे में लाया जा सके। इन प्रयासों के जरिए सरकार की यह कोशिश भी है कि वैसे जरूरतमंदों को भी रोजगार दिया जा सके जो किन्हीं वजहों से स्वरोजगार को नहीं अपना पाते हैं।

इतनी बड़ी आबादी वाले देश में सरकार के लिए सबको नौकरी देना संभव नहीं है। इसलिए सरकार रोजगार सृजन के पारंपरिक तौर-तरीकों की बजाय ऐसे गैर-परंपरागत विकल्पों में भी अवसर तलाश रही है जिनसे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के दायरे में लाया जा सके।

नए अवसर पैदा करने के गैर-परंपरागत विकल्पों से शहरों के साथ-साथ ग्रामीण भारत में भी रोजगार और स्वरोजगार का सृजन हो रहा है। स्टार्टअप इंडिया, इंटर्नशिप योजना, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी जैसी दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं जो युवाओं को ध्यान में रखकर बनी हैं जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है। केंद्र की नीतियों एवं निर्णयों से कृषि क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है। जब सरकार ने गोबरधन योजना के तहत देश में सैकड़ों गोबरगैस प्लांट बनाए और देश की सैकड़ों कृषि मंडियों को ई-नाम योजना से जोड़ने का काम शुरू किया, तो इससे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने। मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग से लेकर रिन्यूबल एनर्जी और ऑर्गेनिक फार्मिंग तक, स्पेस सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर तक, टूरिज्म से लेकर वेलनेस तक, हर सेक्टर में नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी अगर कोई युवा करियर बनाना चाहे तो उसके लिए भी आधुनिक सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं।

हालांकि, केंद्र में अभी भी करीब 10 लाख पद खाली पड़े हैं। राज्यों में तो यह संख्या और भी ज्यादा है। यह सही है कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में सबको नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन जो पद खाली हैं उन पर ही भर्तियां हो जाएंगी तो न सिर्फ युवाओं को इसका लाभ मिलेगा, बल्कि सरकार के लिए भी रोजगार की चुनौतियों से निपटने में आसानी होगी।■

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

'इरमा' बनेगा देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय

सहकारी आंदोलन के जनक त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर होगा यह विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय गठन के लिए संसद के अगले सत्र में पेश किया जा सकता है विधेयक

सहकारिता में युवाओं की भागीदारी बढ़ाएगा इरमा

युवा सहकार टीम

देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय बनाने का रास्ता साफ हो गया है। गुजरात के आणंद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट (इरमा) को अब सहकारिता विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और नेशनल कोऑपरेटवि यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) के अध्यक्ष दिलीप संघाणी की इस विश्वविद्यालय को बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस शीर्ष सहकारी शैक्षिक संस्थान का नामकरण भारत में सहकारी आंदोलन के जनक स्वतंत्रता सेनानी त्रिभुवन दास पटेल के सम्मान में किया गया है। इरमा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित एक बिजनेस स्कूल है जिसकी स्थापना 1979 में दुग्ध क्रांति के जनक डॉ. वर्गीस कुरियन ने की थी।

भारतीय सहकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर इरमा में पढ़े मेधावी ही काम कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह आदि भी इस प्रतिष्ठित संस्थान का दौरा कर चुके हैं। खास बात यह है कि जहां यह इंस्टीट्यूट है उसी आणंद शहर में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का कार्यालय और अमूल का मुख्य प्लांट है। यह शहर सहकारिता का जाना माना नाम है। दरअसल, लंबे समय से गुजरात के इरमा या फिर पुणे स्थित वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट (वैमनीकॉम) में से किसी एक को सहकारिता विश्वविद्यालय बनाने की संभावना थी, जिसमें इरमा ने बाजी मार ली। विश्वविद्यालय बनाने के लिए इरमा के आसपास पर्याप्त जमीन मौजूद हैं। वर्तमान में इरमा में पूर्णकालिक और अंशकालिक पीजी कोर्स संचालित होते हैं और छात्रों को एमबीए की डिग्री प्राप्त होती है।

कानून के जरिये बनेगा विश्वविद्यालय

इस सहकारी विश्वविद्यालय को बनाने के लिए संसद के आगामी सत्र में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। सहकारी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट शिक्षा एवं ट्रेनिंग देने के लिए इस संस्थान को देश का सबसे बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। वर्ल्ड कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष बिनोद आनंद का कहना है कि सरकार के 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को साकार करने के लिए देश में एक सहकारिता विश्वविद्यालय की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जो अब पूरी होने जा रही है।

सहकारिता ग्रामीण विकास की धुरी है और इसमें ग्रामीण भारत व किसानों की समृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। इसीलिए भारत में सहकारिता की उच्चस्तरीय पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय खोलने के बारे में गंभीरता से पहल की गई है। इस विश्वविद्यालय के बनने से देश के सहकार क्षेत्र में शिक्षित एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही, सहकारिता क्षेत्र ट्रेनिंग व टेक्नोलॉजी से लैस होकर आगे बढ़ेगा। सहकारिता विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों को दुनिया के सहकारिता क्षेत्र में चल रहे नवाचारों व ज्ञान-विज्ञान के बारे में जानने एवं सीखने का मौका मिलेगा।

युवाओं को रोजगार
लीक से हटकर अवसर बनाने की कोशिश

सीधे नौकरी देने के परंपरागत तरीकों की बजाय स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के गैर-परंपरागत उपायों को दिया जा रहा बढ़ावा

केंद्र की नीतियों और निर्णयों के कारण ग्रामीण भारत में भी रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों का हो रहा सृजन

स्टार्टअप इंडिया, इंटर्नशिप योजना, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी जैसी दर्जनों योजनाएं युवाओं को ध्यान में रखकर बनीं

युवा सहकार टीम

पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था, 'भारत की प्रगति तभी हो सकती है जब भारत के ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति होगी।' पूर्व प्रधानमंत्री की उक्ति को चरितार्थ करने के लिए जरूरी है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके उपलब्ध कराए जाएं क्योंकि किसी भी देश का विकास उसके युवाओं के श्रम, सामर्थ्य और नेतृत्व से ही होता है। भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक देश की ज्यादातर युवा आबादी को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होंगे। हालांकि, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में सरकार के लिए सबको नौकरी देना संभव नहीं है। इसलिए सरकार भी रोजगार सृजन के पारंपरिक तौर-तरीकों की बजाये ऐसे गैर-परंपरागत विकल्पों में अवसर तलाश रही है जिनसे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के दायरे में लाया जा सके। इन प्रयासों के जरिए सरकार की यह कोशिश भी है कि वैसे जरूरतमंदों को भी रोजगार दिया जा सके जो किन्हीं वजहों से स्वरोजगार को नहीं अपना पाते हैं।

केंद्र सरकार की इन कोशिशों से न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण भारत में भी रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनने लगे हैं। कृषि क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है। जब सरकार ने गोबरधन योजना के तहत देश में सैकड़ों गोबरगैस प्लांट बनाए, तो इससे बिजली तो पैदा हुई ही, हजारों नौजवानों को नौकरी भी मिली। इसी तरह, देश की सैकड़ों कृषि मंडियों को ई-नाम योजना से जोड़ने का काम शुरू किया गया, तो इसने भी नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए रास्ते खोले। वहीं, पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के फैसले से किसानों की मदद तो हुई ही, शुगर सेक्टर में नई

नौकरी के भी मौके बने। यही नहीं, लगभग 9 हजार किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन से किसानों को नया बाजार बनाने में मदद मिली और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी मिले।

सरकार अन्न भंडारण के लिए हजारों गोदाम बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना की शुरूआत कर चुकी है। इन गोदामों का निर्माण भी बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के मौके लाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की है। सरकार का लक्ष्य देश के हर नागरिक को बीमा सुरक्षा से जोड़ने का है। इससे भी बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के मौके बनेंगे। स्टार्टअप इंडिया, इंटर्नशिप योजना, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ड्रोन दीदी अभियान, लखपति दीदी अभियान, बैंक सखी योजना जैसी दर्जनों योजनाएं युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं। इनसे देश के युवक-युवतियों के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर बन रहे हैं।

ऐसा नहीं है कि गैर परंपरागत तरीकों ने केवल ग्रामीण युवाओं के लिए ही रोजगार के अवसर पैदा किये हैं। पढ़े-लिखे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोला और डिफेंस सेक्टर में भी मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है। इसका सबसे ज्यादा लाभ युवाओं को ही मिला है। आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। इसकी बदौलत ही भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया है। साथ ही, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको-सिस्टम बना है जिसमें करीब 16 लाख युवा काम कर रहे हैं। आज भारत मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। रिन्यूबल एनर्जी से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तक, स्पेस सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर तक, टूरिज्म से लेकर वेलनेस तक, हर सेक्टर में नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। इतना ही नहीं, स्पोट्र्स में भी अगर कोई युवा करियर बनाना चाहे तो उसके लिए भी आधुनिक व्यवस्थाएं बन रही हैं। पहले सुविधाओं और ट्रेनिंग के अभाव में इस क्षेत्र की ओर कम ही युवा उन्मुख हो पाते थे। जो स्पोट्र्स में आते भी थे उन्हें भविष्य की चिंता लगी रहती थी। मगर खेलो इंडिया जैसी खेल को बढ़ावा देने वाली योजनाओं से युवाओं में अब इस बात को लेकर भरोसा बढ़ा है कि अगर वह खेल में अपना करियर बनाना चाहे तो वह असफल नहीं होगा क्योंकि अब उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं और टूनामेंटों का समर्थन मिल रहा है।

युवा प्रतिभा को निखारने की जिम्मेदारी

स्टार्टअप्स ने पैदा की 16 लाख नौकरियां

उद्यमिता को बढ़ावा देने और ज्यादा से ज्यादा युवा उद्यमी बनाने के लिए शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना की बदौलत जॉब मार्केट में नए अवसर बढ़ते जा रहे हैं। इससे न सिर्फ देश के युवा सफल उद्यमी बन रहे हैं, बल्कि रोजगार सृजन में भी ये अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये रोजगार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, स्टार्टअप की बदौलत देश में 16 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है।

2016 में अपनी शुरूआत के बाद से डीपीआईआईटी द्वारा संचालित स्टार्टअप इंडिया पहल भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने में गेम चेंजर साबित हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, युवा उद्यमी नए विचार, तकनीकी, इंटरनेट और उपलब्ध मानव संसाधनों की सहायता से सफल व्यापारी साबित हो रहे हैं। फिनटेक, एडुटेक, हेल्थ टेक और ई कॉमर्स के क्षेत्र में स्टार्टअप का प्रचलन बढ़ा है। देश में इसके लिए उपलब्ध इकोसिस्टम, वैश्विक पहुंच और सरकारी वित्तीय सहायता आदि की वजह से स्टार्टअप को सफल होने का बेहतर माहौल मिला है। यही वजह है कि भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है, जहां 100 से अधिक यूनिकॉर्न पंजीकृत हुए हैं। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसे स्टार्टअप से है जिसका वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर हो गया हो या इसे पार कर गया हो।

डीपीआईआईटी के अनुसार, भारत के सिलिकॉन वैली (बेंगलुरु) से शुरू हुए स्टार्टअप ने वैश्विक स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। 6 जनवरी, 2025 तक डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 1,58,203 हो गई। इनमें 73 हजार से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक हैं। यह नवाचार और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

केंद्र सरकार ने रोजगार देने के अपने तरीके में बदलाव किया है जिससे शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण भारत में भी रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। कृषि क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है। जब सरकार ने गोबरधन योजना के तहत देश में सैकड़ों गोबरगैस प्लांट बनाए और देश की सैकड़ों कृषि मंडियों को ई-नाम योजना से जोड़ने का काम शुरू किया, तो इससे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने।

आंकड़ों की जुबानी

रोजगार के मोर्चे पर चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अक्टूबर 2024 में शुद्ध औपचारिक रोजगार सृजन घटकर पांच महीने के निचले स्तर 13.4 लाख पर आ गया। यह अक्टूबर 2023 की तुलना में 11.8 प्रतिशत और सितंबर 2024 की तुलना में 28.7 प्रतिशत कम है। सितंबर 2024 में 18.8 लाख अंशधारक ईपीएफओ से जुड़े थे। यह आंकड़ा ज्यादा चिंताजनक इसलिए भी है कि अक्टूबर का महीना त्यौहारी सीजन की शुरूआत माना जाता है जिस दौरान आमतौर पर मांग बढ़ने से भर्तियां बढ़ने की उम्मीद रहती है। मगर पिछले अक्टूबर में ऐसा नहीं हुआ। नई भर्तियां बढ़ने की बजाय घट गई। आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल महीने में ईपीएफओ में जुड़े नए शुद्ध अंशधारकों की संख्या 12.8 लाख थी जो मई में 13.5 लाख, जून में 13.9 लाख, जुलाई में 16.1 लाख और अगस्त में 15.8 लाख रही।

आज भारत मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। रिन्यूबल एनर्जी से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तक, स्पेस सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर तक, टूरिज्म से लेकर वेलनेस तक, हर सेक्टर में नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी अगर कोई युवा करियर बनाना चाहे तो उसके लिए भी आधुनिक व्यवस्थाएं बन रही हैं।

शिक्षा व्यवस्था पर होती है। देश की प्रगति को गति देने और एक नए भारत के निर्माण के लिए युवा प्रतिभाओं को पोषित करना बहुत जरूरी है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जरूरतों को देखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली की ओर ले जा रही है जो छात्रों को नए अवसर प्रदान करती है। पहले पाबंदियों के कारण जो शिक्षा व्यवस्था छात्रों पर बोझ बन जाती थी, नई शिक्षा नीति अब उन्हें नए विकल्प दे रही है। अटल टिंकरिंग लैब्स और आधुनिक पीएम-श्री स्कूलों के जरिये बचपन से ही इनोवेटिव माइंडसेट को गढ़ा जा रहा है। पहले ग्रामीण युवाओं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के युवाओं के लिए भाषा एक बहुत बड़ी दीवार थी। नई नीति के तहत उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाई और परीक्षा की नीति बनाई गई। युवाओं को अब 13 भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं देने का विकल्प दिया गया है जिससे उनके लिए रोजगार पाना पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो गया। बॉर्डर जिले के युवाओं को ज्यादा मौका देने के लिए सरकारी नौकरियों में उनका कोटा बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर इलाके के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए विशेष भर्ती रैलियां की जा रही हैं।

दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संगठन के लिए

नवनियुक्त 71,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें से 50,000 से अधिक युवाओं को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में नौकरी मिली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, 'पिछले डेढ़ वर्ष में सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की है। ये नौकरियां पूरी पारदर्शिता के साथ दी गई हैं।' हालांकि, सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि अभी भी केंद्र में करीब 10 लाख पद खाली पड़े हैं। अगर इन पदों पर जल्द भर्तियां की जाए, तो न सिर्फ युवाओं को इसका लाभ मिलेगा, बल्कि सरकार के लिए भी रोजगार की चुनौतियों से निपटने में आसानी होगी। सरकार की चिंता पेंशन के बढ़ते बोझ को लेकर भी है जो खजाने पर ज्यादा दबाव डाल रही है। इसकी वजह से विकास की अन्य योजनाएं प्रभावित होती हैं। यह भी एक बड़ा कारण है जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार स्वरोजगार और रोजगार के गैर-परंपरागत तरीके अपनाने को बढ़ावा दे रही है।■

संकट में नए अवसरों की तलाश

वैश्विक बाजार में प्राकृतिक हीरे की मांग में आई कमी के चलते सूरत के हीरा कारीगर अब सोने के गहने बनाने में हाथ आजमा रहे हैं। हीरा काटने और पॉलिश करने वाली सूरत की इकाइयां मौजूदा कारोबारी अनिश्चितता से निपटने के लिए आभूषण निर्माण में विविधता ला रही हैं। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) के अध्यक्ष विपुल शाह के अनुसार, 'सूरत की हीरा इकाइयों ने धीरे-धीरे आभूषण निर्माण में जॉब वर्क करना शुरू कर दिया है। भारत और विदेशों दोनों में आभूषणों की मांग बढ़ रही है। इसलिए वे इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।'

सूरत के हीरा उद्योग में वर्तमान में 5,000 इकाइयां हीरा कटाई और पॉलिश का काम करती हैं जिनमें लगभग 8,00,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। मांग में कमी के चलते इनके सामने रोजगार का संकट है। हीरों की मांग में जल्द सुधार नहीं होने की आशंका के चलते ही जीजेईपीसी ने लगभग छह महीने पहले आभूषण बनाने का कोर्स शुरू किया था। हजारों हीरा कारीगर यह कोर्स कर सोने के गहने बना रहे हैं। वे ज्यादातर जड़ाऊ आभूषण बना रहे हैं। हीरा उद्योग के जानकारों का कहना है कि सूरत की 500 से ज्यादा इकाइयों ने हीरा कटाई और पॉलिशिंग के अलावा आभूषण निर्माण का काम भी शुरू कर दिया है। जीजेईपीसी के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान कटे और पॉलिश किए हुए हीरे के निर्यात में 19 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि सामान्य सोने के आभूषणों में 2.48 प्रतिशत और जड़ाऊ आभूषणों के निर्यात में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

पीएम इंटर्नशिप योजना की हुई शुरूआत

रोजगार की बढ़ेगी संभावना

युवा सहकार टीम

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भी सरकार की नई सोच का उदाहरण है। सरकार ने इस योजना की शुरूआत कर दी है। इसके तहत अगले पांच वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। यह योजना देश में कुशल पेशेवरों की अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए डिजाइन की गई है। इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी। शुरूआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1.25 लाख युवाओं का इंटर्नशिप के लिए चयन किया गया है। यह रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का एक परिवर्तनकारी प्रयास है जो नियोक्ताओं और प्रतिभागियों दोनों के लिए बेहतर है। इसका उद्देश्य युवा उम्मीदवारों को उद्योग जगत से जोड़कर कार्यबल में कौशल अंतर को दूर करना और प्रतिभागियों को भविष्य के नौकरी बाजार के लिए तैयार करना है।

इस योजना के तहत शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को 12 महीने तक हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें से 4,500 रुपये केंद्र सरकार की ओर से और 500 रुपये कंपनी की ओर से मिलेंगे। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में आएगी। इसके अलावा, सरकार उन्हें 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता देगी। साथ ही, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत उनका बीमा भी होगा।

पीएम इंटर्नशिप योजना देश के युवाओं के लिए शीर्ष उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है। यदि कोई युवा वास्तविक दुनिया के कौशल का निर्माण करते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाने के तरीकों की तलाश में है, तो यह योजना उनके लिए बेहतर है। यह योजना इंटर्नशिप कार्यक्रम से कहीं ज्यादा देश और यहां के युवाओं के उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम है। यह योजना युवाओं को व्यावसायिक अनुभव प्रदान कर उनकी रोजगार संभावनाओं को मजबूत करेगी। इच्छुक अभ्यर्थी पीएम इंटर्नशिप पोर्टल (pminternship.mca.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

क्या है पात्रता

इस योजना के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 21-24 वर्ष होनी चाहिए। दसवीं, बारहवीं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाधारी और ग्रेजुएट (बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीफार्मा) युवक-युवती इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई कहीं से फुल टाइम कोर्स या फुल टाइम जॉब कर रहा हो तो वह इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। डिस्टेंस लर्निंग वाले आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदक के परिवार (खुद/पति या पत्नी/ माता-पिता) की सालाना आमदनी 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो। आवेदन करने के बाद कंपनियां खुद ही आपसे संपर्क कर इंटर्नशिप के लिए बुलाएंगी।

इस योजना के तहत कंपनियों का चयन पिछले तीन वर्षों में उनके द्वारा खर्च की गई कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) धनराशि के आधार पर किया गया है। इनमें विभिन्न कंपनियों के साथ-साथ बैंक और वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं। ■

एनवाईसीएस के सीईओ बने डॉ. रामचंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी

एनवाईसीएस के नए सीईओ डॉ. रामचंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी (बाएं से तीसरे) का स्वागत करते संगठन के चेयरमैन राजेश पांडे एवं अन्य।

युवा सहकार टीम

देश के युवाओं का मार्गदर्शन करने को प्रतिबद्ध प्रमुख सहकारी संस्था नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) ने डॉ. रामचंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने अपना पदभार दिसंबर 2024 में ग्रहण कर लिया। मैनेजमेंट स्टडीज में डॉक्टरेट (म्यूचुअल फंड और सीएम) डॉ. कुलकर्णी को पेशेवर जिंदगी का 35 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है।

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के लेखा प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हुए डॉ. कुलकर्णी को परिणामोन्मुखी पेशेवर माना जाता है। एमएसआरटीसी से उनका लंबा जुड़ाव रहा है। इस विभाग में वे संभागीय लेखा अधिकारी से लेकर विभिन्न पदों पर रहते हुए लेखा प्रमुख पद तक पहुंचे। कुछ समय के लिए उन्हें प्रतिनियुक्ति पर 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कारोबार के व्यावसायिक मिश्रण वाले एस. टी. कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का प्रशासनिक प्रमुख बनाया गया था। इस दौरान उन्होंने बैंक के विकास और कार्यान्वयन में प्रबंधन कौशल का बेहतर प्रदर्शन किया।

डॉ. कुलकर्णी को कंपनी के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने, सरकारी नियमों और विनियमों के अनुपालन में परिचालन को संभालने में कुशलता हासिल है। इसके अलावा, वित्तीय प्रक्रियाओं की संकल्पना और कार्यान्वयन में कार्यशील पूंजी, मुनाफे की निगरानी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के निर्माण सहित व्यापक अनुभव है।

डॉ. कुलकर्णी को कंपनी के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने, सरकारी नियमों और विनियमों के अनुपालन में परिचालन को संभालने में कुशलता हासिल है। इसके अलावा, वित्तीय प्रक्रियाओं की संकल्पना और कार्यान्वयन में कार्यशील पूंजी, मुनाफे की निगरानी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के निर्माण सहित व्यापक अनुभव है। किसी भी संस्थान की जरूरतों और लक्ष्यों का पता लगाने, संचालन को सुव्यवस्थित करने, नई अवधारणाओं की कल्पना करने में भी उन्हें महारत हासिल है।

एनवाईसीएस के चेयरमैन राजेश पांडे ने डॉ. कुलकर्णी की नियुक्ति को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनके लंबे पेशेवर अनुभवों का लाभ निश्चित तौर पर संगठन को मिलेगा जिससे युवाओं को फायदा होगा। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में युवाओं की यह सहकारी संस्था नई ऊंचाइयों को छुएगी।

युवा विकास से राष्ट्र विकास के सूत्र को अपना ध्येय मानते हुए नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) देश के युवाओं का मार्गदर्शन करने और ऐसे सभी मौकों से अवगत कराने का प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे उनकी जिंदगी में सुधार आ सके। डॉ. रामचंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी एनवाईसीएस के इस ध्येय को आगे बढ़ाने में अपनी पेशेवर कुशलता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे।■

10 हजार नए एम-पैक्स, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ

सहकारिता लिखेगी नई इबारत

10 हजार नए एम-पैक्स, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं अन्य मंत्री।

दो लाख नए पैक्स बनाने का लक्ष्य समय से पहले होगा पूरा : अमित शाह

कंप्यूटरीकरण से पैक्स की बढ़ी पारदर्शिता, सहकारिता के विस्तार से महिलाओं व युवाओं को मिल रहे रोजगार के नए अवसर

तीन नई राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं से जुड़े पैक्स, अब ऑर्गेनिक उत्पाद, बीज उत्पादन और निर्यात में सक्रिय होंगे जिससे किसानों की समृद्धि सुनिश्चित होगी

युवा सहकार टीम

सहकारिता का जमीनी स्तर पर विस्तार करना और इसे महिलाओं एवं युवाओं के लिए रोजगार का बेहतर माध्यम बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। इसके लिए देश के सभी पंचायतों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की मौजूदगी का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए सरकार ने वर्ष 2027 तक उन पंचायतों में दो लाख नए पैक्स के गठन का निर्णय लिया है जहां अभी पैक्स नहीं हैं। इनमें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स), डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियां भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में 10,000 नवगठित एम-पैक्स, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया। इन नवगठित सहकारी समितियों के माध्यम से देश के गांवों में न सिर्फ सहकारिता का जन-जन तक विस्तार होगा, बल्कि सहकारिता आंदोलन को नई मजबूती मिलेगी और इस क्षेत्र में नई इबारत लिखी जाएगी।

इन सहकारी समितियों के पंजीकरण में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) ने बड़ी भूमिका निभाई है। नाबार्ड पहले चरण में 22,750 पैक्स और दूसरे चरण में 47,250 पैक्स बनाएगा। इसी प्रकार, एनडीडीबी 56,500 नई सहकारी समितियां बनाएगा और 46,500 मौजूदा समितियों को सुदृढ़ करेगा। एनएफडीबी 6,000 नई मत्स्य सहकारी समितियां बनाने और 5,500 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों के सशक्तिकरण का कार्य करेगा। इनके अलावा राज्यों के सहकारी विभाग 25,000 नए पैक्स बनाने का दायित्व निभाएंगे।

इस मौके पर अमित शाह ने विश्वास जताया कि तय समय से पहले ही दो लाख पैक्स का

गठन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'नए मॉडल बायलॉज के साथ अब तक 11,695 नई प्राथमिक सहकारी समितियां पंजीकृत हुई हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के त्रिस्तरीय सहकारिता ढांचे को सबसे ज्यादा ताकत प्राथमिक सहकारी समिति ही दे सकती है। दो लाख नए पैक्स के गठन के बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से किसानों की उपज को वैश्विक बाजार में पहुंचाना बड़ा सरल हो जाएगा। सरकार का मानना है कि 'सहकार से समृद्धि' का ध्येय तभी सफल हो पाएगा जब हर पंचायत में सहकारिता की उपस्थिति हो और वहां किसी न किसी रूप में काम करे। प्रशिक्षित मानव संसाधन के अभाव में इन सभी गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन संभव नहीं है। ऐसे में प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया गया है। इससे पैक्स के सदस्यों और कर्मचारियों को संपूर्ण प्रशिक्षण देने का अभियान संपन्न किया जाएगा। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए हर जिला सहकारी रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिससे पैक्स के सचिव एवं कार्यकारिणी के सदस्यों का अच्छा प्रशिक्षण सुनिश्चित हो सके।'

32 नई गतिविधियों से जुड़े पैक्स

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सबसे बड़ा कार्य सभी पैक्स के कंप्यूटरीकरण का हुआ है। पैक्स को आर्थिक तौर पर व्यवहारिक बनाने के लिए इसके कार्यों को विस्तार दिया गया है और इसे 32 प्रकार की नई गतिविधियों से जोड़ा गया है। सरकार ने पैक्स को बहुआयामी बनाकर उन्हें पेट्रोल एवं डीजल पंप खोलने, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर बनने, कॉमन सर्विस सेंटर एवं जनऔषधि केंद्र खोलने, अन्न भंडारण, उर्वरक और जल वितरण आदि गतिविधियों के साथ जोड़ा है। पैक्स के विस्तार के लिए दृश्यता, प्रासंगिकता, व्यवहार्यता और जीवंतता का ध्यान रखा गया है। पैक्स जब कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) बन जाता है तो गांव का हर नागरिक किसी न किसी रूप में इससे जुड़ जाता है। इसी प्रकार, सरकार ने पैक्स की प्रासंगिकता भी बढ़ाई है। जब पैक्स एलपीजी वितरण, डीजल-पेट्रोल वितरण आदि का काम करते हैं, तो उनकी जीवंतता अपने आप बढ़ जाती है। पैक्स के बहुद्देश्यीय होने से इसे विस्तार मिला है जिससे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

इसी तरह, कंप्यूटरीकरण और टेक्नोलॉजी से पैक्स में पारदर्शिता आएगी, सहकारिता का जमीनी स्तर पर विस्तार होगा और ये महिलाओं और युवाओं के रोजगार का माध्यम बनेगा। साथ ही पैक्स कृषि संसाधनों की सरल उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रीय स्तर की तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियों व भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल), नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से पैक्स ऑर्गेनिक उत्पादों, बीजों और निर्यात के साथ किसानों की समृद्धि के रास्ते भी खोलेगा। इससे सामाजिक और आर्थिक समानता आएगी, क्योंकि नए मॉडल बायलॉज में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इससे देश में सामाजिक समरसता बढ़ेगी।■

सभी प्राथमिक डेयरी समितियों को मिलेगा माइक्रो एटीएम

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 10 हजार सहकारी समितियों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो एटीएम देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत आने वाले दिनों में हर प्राथमिक डेयरी को माइक्रो एटीएम दिया जाएगा। माइक्रो एटीएम और रुपे किसान क्रेडिट कार्ड से सभी किसान को कम खर्च पर ऋण मिल सकेगा। 10 हजार नए एम-पैक्स, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी मौके पर 25 दिसंबर, 2024 को किया गया। अमित शाह ने कहा कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। संविधान में 97वां संशोधन उनके कार्यकाल में ही हुआ था और इसके माध्यम से लंबे समय से हाशिये पर पड़ी सहकारिता को महत्व मिला था।

नाबार्ड पहले चरण में 22,750 पैक्स और दूसरे चरण में 47,250 पैक्स बनाएगा। इसी प्रकार, एनडीडीबी 56,500 नई सहकारी समितियां बनाएगा और 46,500 मौजूदा समितियों को सुदृढ़ करेगा। एनएफडीबी 6,000 नई मत्स्य सहकारी समितियां बनाने और 5,500 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों के सशक्तिकरण का कार्य करेगा। इनके अलावा राज्यों के सहकारी विभाग 25,000 नए पैक्स बनाने का दायित्व निभाएंगे।

ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देंगे पैक्स

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एनसीओएल की समीक्षा बैठक करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह।

देश के सभी पैक्स को ऑर्गेनिक मिशन से जोड़ कर जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने का अभियान चलाने का अमित शाह ने दिया निर्देश

एनसीओएल की समीक्षा बैठक में केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने पैक्स को ऑर्गेनिक उत्पादों और बीजों की बिक्री का केंद्र बनाने को भी कहा

बीबीएसएसएल की समीक्षा बैठक में बीज उत्पादन के लिए पानी और कीटनाशक के उपयोग को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत की

युवा सहकार टीम

ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक मिशन को पैक्स से जोड़े जाने का सरकार ने निर्देश दिया है। साथ ही, सभी पैक्स को ऑर्गेनिक उत्पादों और बीजों की बिक्री का केंद्र बनाने का आह्वान किया गया है। सहकारिता के माध्यम से ऑर्गेनिक खेती और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) का गठन किया गया है। इसका मकसद ग्राहकों को प्रमाणित जैविक उत्पाद उपलब्ध कराने और जैविक खेती करने वाले किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है।

वर्ष 2024 के अंत में एनसीओएल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, 'देश के सभी पैक्स को ऑर्गेनिक मिशन से जोड़कर ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने का अभियान चलाना चाहिए। ऑर्गेनिक उत्पादों के स्रोत और उत्पादों की शुद्धता पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए एनसीओएल को अपने 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड के तहत किसानों से ग्राहकों तक प्रामाणिक जैविक उत्पादों की एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर जोर देना चाहिए। बाजार में ग्राहकों के लिए शुद्ध प्रमाणिक जैविक उत्पाद सुलभ हो सकें इसके लिए एनसीओएल को प्रत्येक 'भारत ऑर्गेनिक्स' उत्पाद के बैच का अनिवार्य परीक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।' उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमूल की डेयरियों और एनडीडीबी की संस्थाओं से जुड़े किसानों को भी आर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।

किसानों को उनके ऑर्गेनिक उत्पादों के बदले उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ताकि वे इसकी खेती की दिशा में प्रेरित होकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। अमित शाह ने एनसीओएल और सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे अमूल के साथ भारत ऑर्गेनिक्स पर एक बैठक कर ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक अरहर दाल जैसे उत्पादों के दामों को इस प्रकार से निश्चित

पारंपरिक 'मीठे' या लुप्तप्राय बीजों के संवर्द्धन व संरक्षण के साथ-साथ पोषक तत्वों को कम किए बिना दलहन और तिलहन के बीजों का उत्पादन बढ़ाना बीबीएसएसएल की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही, छोटे किसानों की उपज और उनकी फसल की परिपक्वता अवधि बढ़ाने की दिशा में काम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

करें जिससे किसानों को फायदा पहुंचे और वे ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज्यादा प्रेरित हों। एक बार अगर किसान को ज्यादा दाम मिलने की शुरूआत होगी तो निश्चित ही किसान धीरे-धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ प्रोत्साहित होंगे। जिस प्रकार से ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है, उससे निश्चित रूप से पूरे देश में इन उत्पादों की मांग कई गुना बढ़ेगी।

अमित शाह ने बैठक में कहा कि देश के सभी पैक्स को कृषि उत्पाद का स्रोत, ऑर्गेनिक उत्पादों एवं बीजों की बिक्री का केंद्र बनाया जाए। इससे एनसीओएल, एनसीईएल (नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड) और बीबीएसएसएल (भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड) जैसी राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, नई बनने वाली 2 लाख सहकारी समितियों में कम से कम एक ऐसे युवा किसान को जोड़ा जाना चाहिए जो आगे चलकर स्थानीय सहकारी ढांचे को मजबूत बनाने में प्रेरक का काम कर सकें। पैक्स के सदस्यों के साथ-साथ किसानों के समुचित प्रशिक्षण की भी उन्होंने वकालत की। उनके मुताबिक, नाबार्ड को सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर नए पैक्स की ऐसी कार्यप्रणाली निर्धारित करनी चाहिए जिससे प्रत्येक किसान को उसकी क्षमता के अनुरूप ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

बीबीएसएसएल से 20 हजार समितियों को जोड़ने का लक्ष्य

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की एक अन्य समीक्षा बैठक में बीज उत्पादन के लिए पानी और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने पर ध्यान देने का सुझाव देते हुए अगले वित्त वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर की इस सहकारी संस्था से 20,000 सहकारी समितियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा। बैठक में उन्होंने कहा कि पारंपरिक 'मीठे' या लुप्तप्राय बीजों के संवर्द्धन व संरक्षण के साथ-साथ पोषक तत्वों को कम किए बिना दलहन और तिलहन के बीजों का उत्पादन बढ़ाना बीबीएसएसएल की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही, छोटे किसानों की उपज और उनकी फसल की परिपक्वता अवधि बढ़ाने की दिशा में काम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

बीबीएसएसल देश के परंपरागत मीठे बीजों के संग्रहण और संरक्षण की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। बीज उत्पादन बढ़ाने से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 10 साल का रोडमैप बनाने और उसकी निरंतर समीक्षा करने पर सहकारिता मंत्री ने जोर दिया। अमित शाह के मुताबिक, सभी सहकारी संस्थाओं को सभी किसानों को प्रमाणित बीज से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बीबीएसएसल को बीज उत्पादन, शोध और संवर्द्धन की दिशा में काम करने वाले सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और प्रयोगशालाओं का उपयोग करना चाहिए।

बीबीएसएसएल द्वारा चालू रबी सीजन 2024-25 में छह राज्यों में 5,596 हेक्टेयर क्षेत्र में आधार और प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 8 फसलों की 49 किस्मों के 1,64,804 क्विंटल बीज उत्पादन का अनुमान है। राष्ट्रीय स्तर की इस सहकारी संस्था ने वर्ष 2032-33 तक 18,000 करोड़ रुपये का टर्नओवर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अपने परिचालन के बाद से इसने मुख्य रूप से गेहूं, मूंगफली, जई और बरसीम जैसी चार फसलों के 41,773 क्विंटल बीज बेचे/वितरित किए हैं।

दाम स्थिर रखने को महाराष्ट्र प

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नेफेड) देश की सर्वोच्च कोऑपरेटिव मार्केटिंग संस्था है। यह किसानों की कोऑपरेटिव है जिसका उद्देश्य कृषि, बागवानी और वन उपज की मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और स्टोरेज को व्यवस्थित करना, बढ़ावा देना और विकसित करना है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद से लेकर उन्हें उचित कीमत पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया और अन्य मसलों पर नेफेड के एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर **सुनील सिंह** से **एसपी सिंह** और **अभिषेक राजा** ने विस्तृत बातचीत की। पेश हैं उसके प्रमुख अंशः

किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसे नेफेड द्वारा अमल में लाया जाता है? इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर कैसे क्रियान्वित किया जाता है?

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग की एक प्रमुख योजना है जिसे मूल्य समर्थन योजना के माध्यम से लागू किया जाता है। नेफेड प्रत्येक फसल वर्ष में तिलहन, दलहन और कोपरा के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से इनकी खरीद करता है। इसके अलावा, मूल्य स्थिरीकरण प्रबंधन कोष (पीएसएफ) के तहत राष्ट्रीय स्तर पर दलहन बफर के लिए बाजार दर पर दालों की खरीद भी करता है। साथ ही, प्याज की भी खरीदी और संग्रहण करता है। जमीनी स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां जिनमें ज्यादातर पैक्स होते हैं, पंजीकृत किसानों से फसलों की खरीद करती हैं। नेफेड ने एक पोर्टल 'ई-समृद्धि' विकसित किया है जो किसानों के पंजीकरण से लेकर उनके द्वारा की गई फसलों की बिक्री और उनके बैंक खाते में सीधे भुगतान (डीबीटी) तक की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

मूल्य समर्थन योजना में किन-किन फसलों की खरीदी होती है?

केंद्र सरकार 23 कृषि जिंसों का एमएसपी निर्धारित करती है। इनमें से 16 जिंसों की खरीद नेफेड द्वारा एमएसपी पर की जाती है। दलहन फसलों के अंतर्गत चना, मसूर, अरहर, उड़द और मूंग की खरीद किसानों से की जाती है। जबकि तिलहन फसलों में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम, तोरिया, तिल और नाइजर की खरीद होती है। दक्षिण भारत में मिलिंग कोपरा, बॉल कोपरा और बिना छिलके वाले नारियल की खरीद नेफेड करता है। फसल वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान 27,649 करोड़ रुपये मूल्य की 81.74 लाख टन तिलहन और दलहन फसलों की खरीद की गई। चालू फसल वर्ष में 21,930 करोड़ रुपये मूल्य की 35.27 लाख टन फसलों की खरीद पहले ही की जा चुकी है। चालू रबी सीजन में सोयाबीन और मूंगफली की खरीद प्रगति पर है।

दालों और प्याज की कीमतों को नियंत्रित रखने में नेफेड कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?

वर्ष 2015 में जब दालों की आपूर्ति में गंभीर बाधा आई थी, तो मैंने ही दालों का बफर स्टॉक बनाने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव पर अमल करते हुए 2015-16 में प्याज के साथ दालों को भी मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) में शामिल कर लिया गया। पीएसएस (मूल्य समर्थन योजना) और पीएसएफ के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दी गई भारी खरीद सहायता ने घरेलू मांग को पूरा

र घटानी होगी प्याज की निर्भरता

करने के लिए किसानों को अधिक दालें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसका नतीजा यह हुआ कि 2015-16 में जहां 1.63 करोड़ टन दालों का उत्पादन हुआ था वह 2021-22 में बढ़कर 2.73 करोड़ टन तक पहुंच गया। चना का उत्पादन 2015-16 के 70 लाख टन के स्तर से लगभग दोगुना होकर 2021-22 में 1.35 करोड़ टन हो गया है। दालों के आयात के साथ-साथ घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने जैसी सभी गतिविधियों में नेफेड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जहां तक प्याज का सवाल है, रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद कई बार इसका मूल्य प्रबंधन चुनौतीपूर्ण होता है। भंडारण योग्य रबी प्याज के बेहतर भंडारण के लिए आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है। इसके अलावा, पूरे भारत में प्याज के उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है, न कि महाराष्ट्र, खासकर नासिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर रहने की। किसानों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में प्याज का उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन इसकी कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए उत्पादन और वितरण की चुनौतियों से निपटने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

दलहन उत्पादक प्रमुख देश कौन से हैं और वे भारत में दलहन की कीमतों को कैसे प्रभावित करते हैं?

भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बना हुआ है। चना और मूंग के मामले में यह लगभग आत्मनिर्भर है। हालांकि, अरहर, मसूर और उड़द के लिए आयात पर निर्भरता बनी हुई है। भारत में मसूर की आपूर्ति ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से होती है। म्यांमार और कुछ अफ्रीकी देश जैसे मोजाम्बिक, तंजानिया, मलावी, सूडान, केन्या अरहर के आपूर्तिकर्ता हैं, जबकि म्यांमार उड़द का एकमात्र आपूर्तिकर्ता था। किसी एक देश पर आयात निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामलों का विभाग नेफेड के साथ मिलकर आपूर्ति के स्रोत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हाल के वर्षों में ब्राजील गुणवत्तापूर्ण उड़द के अच्छे आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। मसूर और अरहर के लिए भी ऑस्ट्रेलिया, रूस और ब्राजील के साथ इसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हमें इसकी आवश्यकता है क्योंकि अभी भी हम लगभग 45-50 लाख टन दालों के आयात पर निर्भर हैं। इन देशों से नियमित आपूर्ति घरेलू कीमतों को नियंत्रित और उचित स्तर पर रखने में मदद करती है।

कोऑपरेटिव में आप युवाओं की भूमिका को कैसे देखते हैं और राष्ट्र निर्माण में उन्हें शामिल करने में नेफेड क्या भूमिका निभा सकता है?

युवा ही देश का वर्तमान और भविष्य हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों से सहकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहा है। डेयरी, मत्स्य पालन, भंडारण, एलपीजी/पेट्रोल पंप आदि सहित 25 से अधिक नए क्षेत्र पैक्स के लिए व्यावसायिक उद्यम के रूप में खोले गए हैं। सहकारी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऐसी सभी योजनाओं से ग्रामीण युवाओं को बहुत लाभ होगा। नेफेड पहले से ही एक जिला एक उत्पाद (ओपीओडी) योजना और अनाज भंडारण योजना लागू कर रहा है। यह सहकारी समितियों में एक नए युग की शुरुआत है। सरकार के इन प्रयासों से निश्चित रूप से किसानों और ग्रामीण आबादी को लाभ होगा।■

पुणे पुस्तक महोत्सव 2024

बने पांच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

पुस्तक महोत्सव में 10 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया

इस दौरान 25 लाख से ज्यादा किताबें बिकीं, 100 से अधिक नई पुस्तकें लॉन्च हुईं

युवा सहकार टीम

आज के समय में जब माना जा रहा है कि पुस्तकों की तरफ लोगों का आकर्षण कम होता जा रहा है, पुणे पुस्तक महोत्सव इस धारणा को निरंतर गलत साबित कर रहा है। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाले पुणे शहर में नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से आयोजित पुस्तक महोत्सव 2024 ने भव्यता और सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल की। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि इस दौरान एक साथ पांच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। तेजी से डिजिटल होते जा रहे जिस युग में पत्र-पत्रिकाओं की तरफ से युवा मुख मोड़ते दिखते हैं उस दौर में पुणे महोत्सव में पुस्तकों की बिक्री में युवाओं की 60 से 70 प्रतिशत हिस्सेदारी सुकून देती है।

महोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी नौ दिन चले इस महोत्सव में शिरकत

की। पुणे पुस्तक महोत्सव के संयोजक और नेशनल युवा कोऑपरेशन सोसाइटी (एनवाईसीएस) की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन राजेश पांडे ने युवा सहकार को बताया, 'पुस्तक महोत्सव का अनुभव इस भ्रांति को गलत साबित करता है कि युवा पीढ़ी में पुस्तकों का मोह खत्म हो रहा है। जिस शिद्दत से इस महोत्सव में युवाओं ने भागीदारी दिखायी है उससे स्पष्ट है कि पुस्तकों की प्रासंगिकता अभी समाप्त नहीं हुई है।'

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने संबोधन में कहा, 'पुस्तक महोत्सव के आयोजन के लिए पुणे सबसे उपयुक्त शहर है। पुणे शहर ने पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त किया है। भविष्य में मुंबई, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर सहित अन्य शहरों में भी इसी तरह के पुस्तक महोत्सव आयोजित किए जाएंगे।' नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता साहित्य के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर आधारित है। साहित्य रचनात्मकता को जीवित रखता है। आज की डिजिटल दुनिया में भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने अत्यधिक महत्व प्राप्त कर लिया है, लेकिन यह मानव बुद्धिमत्ता का स्थान नहीं ले सकती जिसमें रचनात्मकता की शक्ति निहित है। आज के डिजिटल युग में भी साहित्य अपनी रचनात्मकता के माध्यम से मानवीय बुद्धि को प्रासंगिक बनाए रखेगा।

पांच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

पुणे पुस्तक महोत्सव 2024 इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा कि इस दौरान एक साथ पांच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने जिसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से सर्टिफिकेट दिया गया। इस मेले में पहला रिकॉर्ड 'किसी एक लेखक की पुस्तकों की

सबसे बड़ी प्रदर्शनी' के रूप में बना। जैन आचार्य रत्नसुंदर सूरीश्वरजी की 481 पुस्तकों की प्रदर्शनी के रूप में यह रिकॉर्ड बना। इसी तरह, किसी पुस्तक लॉन्च इवेंट के लिए सर्वाधिक यूट्यूब दर्शक के रूप में दूसरा विश्व रिकॉर्ड बना। इसके तहत वर्चुअल पुस्तक लॉन्चिंग ने ऑनलाइन सहभागिता के नए मानक स्थापित किए। सबसे बड़ी पुस्तक मोजेक के तौर पर तीसरा रिकॉर्ड बना। मेले में हजारों पुस्तकों से निर्मित 'सरस्वती यंत्र' का प्रतिरूप बनाया गया था जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यही नहीं, भारतीय संविधान के आवरण का एक स्कल्पचर 97,020 पुस्तकों से बनाया गया जिसने सबसे बड़ी पुस्तक स्कल्पचर के तौर पर विश्व रिकॉर्ड बनाने में सफलता हासिल की। पांचवें गिनीज रिकॉर्ड के रूप में बुक कवर का सबसे बड़ा ऑनलाइन फोटो एलबम बनाया गया। इस एलबम में 11,11,228 डिजिटल बुक कवर को शामिल किया गया।

14-22 दिसंबर तक आयोजित हुए इस पुस्तक मेले को सांस्कृतिक और साहित्यिक पुनर्जागरण के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान न सिर्फ राज्य और देशभर से लोगों की भारी भागीदारी रही, बल्कि साहित्य महोत्सव का समावेश इसका एक उल्लेखनीय आकर्षण था जिसमें 50 से अधिक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हस्तियां एक साथ आईं। इसके अलावा, बाल फिल्म महोत्सव को छात्रों से उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली जिससे यह सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक बन गया।

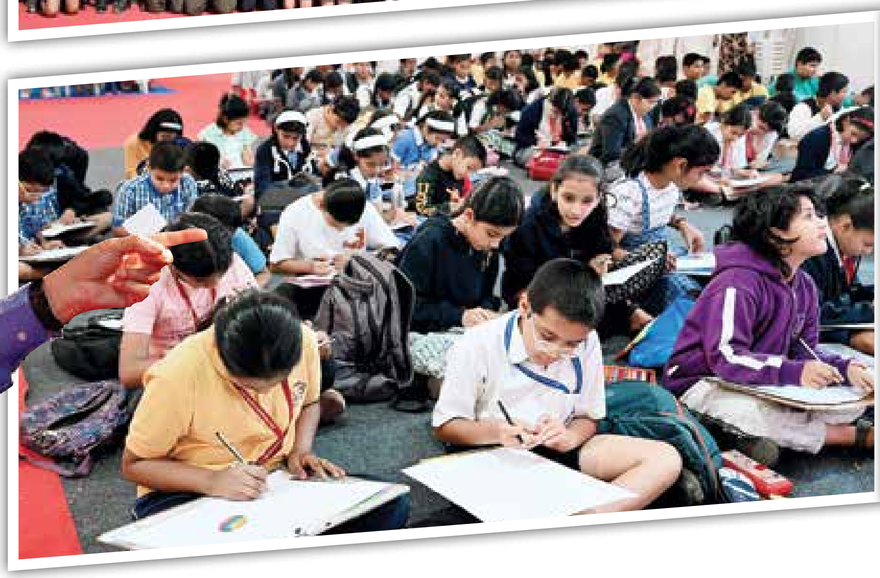

भारतीय संविधान के आवरण का एक स्कल्पचर 97,020 पुस्तकों से बनाया गया जिसने सबसे बड़ी पुस्तक स्कल्पचर के तौर पर विश्व रिकॉर्ड बनाने में सफलता हासिल की।

पुस्तक निस्वार्थ साथीः धर्मेंद्र प्रधान

पुस्तक महोत्सव में हिस्सा लेते हुए प्रधान ने कहा, 'भारत की सभ्यता और संस्कृति में पुणे का अनन्य स्थान है। साहित्य के माध्यम से सभ्यता निरंतर चलती रहती है। साहित्य और भाषा की अभिव्यक्ति के प्रकार का नाम है पुस्तक। इसलिए कभी भी दुनिया के इतिहास की समीक्षा करते हैं, तो सामाजिक जीवन की निरंतरता की जानकारी पुस्तक के माध्यम से मिलती है। माता-पिता के बाद अगर कोई जीवन में निरंतर और निस्वार्थ साथी होता है तो वह पुस्तक है।'

पुणे के फर्गुसन कॉलेज ग्राउंड में हुए इस पुस्तक महोत्सव का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से किया गया था जिसका संयोजन समर्थ युवा फाउंडेशन ने किया था। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय और पुणे नगर निगम का इसमें खास सहयोग था। पुणे पुस्तक महोत्सव पुणे की सांस्कृतिक पहचान की आधारशिला बन गया है और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की राह पर है। माना जा रहा है कि यह महोत्सव निकट भविष्य में पुणे को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। इस महोत्सव में छात्रों, अभिभावकों और युवाओं की जबरदस्त भागीदारी ने पढ़ने और साहित्य को बढ़ावा देने वाले एक आंदोलन को मजबूत किया है जिससे पुणे और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक मजबूत साहित्यिक संस्कृति का मार्ग प्रशस्त हुआ है।■

कैंपस कोऑपरेटिव विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद

शैक्षणिक परिसरों में कोऑपरेटिव के जरिये ग्राहकों से सीधे जुड़ेंगे किसान, गायब होंगे कॉरपोरेट बिचौलिए

किसानों को नया बाजार उपलब्ध कराने को दो साल में बनेंगे 500 कैंपस कोऑपरेटिव

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया और वैमनीकॉम के अलुमनी की है इसमें अहम भूमिका

युवा सहकार टीम

देशभर में फैले शैक्षणिक परिसरों में करोड़ों की संख्या में विभिन्न उत्पादों की आवश्यकता होती है जिसे सामान्यतया बिचौलियों के माध्यम से पूरा किया जाता है। देशभर में 1,100 से अधिक विश्वविद्यालयों और करीब 44,000 कॉलेजों में चार करोड़ से अधिक युवा पढ़ते हैं। ऐसे में इनकी खानपान की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैंपस कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों को सीधे लाभान्वित करने की योजना है। शिक्षा को नया आकार देने और अधिक समावेशी एवं समुदाय उन्मुख परिसरों के निर्माण में भी कैंपस कोऑपरेटिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

इसी दृष्टिकोण के साथ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) और वर्ल्ड इकोनॉमिक कोऑपरेटिव फोरम ने दो वर्षों में 500 कैंपस कोऑपरेटिव बनाने का लक्ष्य रखा है। कैंपस कोऑपरेटिव छात्रों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय समुदायों को कई लाभ प्रदान करती हैं। इसका सबसे प्रमुख लाभ सस्ती वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता है। इससे बिचौलियों और व्यापारियों को खाद्य मूल्य श्रृंखला से हटाकर किसानों को सीधे जोड़ा जाता है जिससे शैक्षणिक कैंपस के ग्राहकों यानी छात्र-छात्राओं को सस्ती दर पर खानपान का सामान मिलने का रास्ता साफ होता है। देश के कुछ शैक्षणिक परिसरों में इसकी शुरूआत हो चुकी है। एनसीयूआई और इफको के चेयरमैन दिलीप संघाणी के मुताबिक, पूरे देश में सहकारी क्षेत्र पर काफी जोर दिया जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन को आगे ले जाने

के लिए युवाओं की सहभागिता बहुत जरूरी है। प्रतिभावान युवाओं को आंदोलन से जोड़ने और नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कैंपस कोऑपरेटिव एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह किसानों को सीधे शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं को सशक्त बनाने और किसानों के लिए समान रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों और किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों के अनुरूप है। इससे कैंपस सहकारी समितियों का विकास करने, सहकारी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी को प्रेरित करने और भारत में एक समृद्ध और टिकाऊ कृषि सहकारी क्षेत्र के दृटिकोण को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सहकारी भागीदारी की क्षमता का उपयोग होने से देश में किसानों और शिक्षा के एकीकरण में एक नई शुरूआत होगी और कृषि स्थिरता और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

कैसे काम करता है कैंपस कोऑपरेटिव

कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल पर कैंपस कोऑपरेटिव काम करता है। पारंपरिक बिजनेस जिसका प्राथमिक लक्ष्य शेयरधारकों या मालिकों के लिए अधिकतम लाभ कमाना है, के विपरीत सहकारी समितियों को उनके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाता है। आम तौर पर सहकारी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों में प्रत्येक सदस्य का समान अधिकार होता है, भले ही उसमें उनका वित्तीय योगदान कुछ भी हो।

कैंपस सहकारी समितियां कई रूप में काम कर सकती हैं। इनमें खाद्य सहकारी समितियां, पुस्तक भंडार और छात्र सेवा सहकारी समितियां शामिल हैं। खाद्य सहकारी समितियां छात्रों द्वारा संचालित किराना स्टोर या कैफे हैं जो छात्रों को स्वस्थ, स्थानीय रूप से प्राप्त और किफायती खाद्य वस्तुएं प्रदान करते हैं। साथ ही, पोषण और सस्टेनिबिलिटी के बारे में शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं।

सहकारिता भरेगी नई उड़ान

देश में अभी गिनती के ही स्टूडेंट कोऑपरेटिव काम कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाने का अभियान शुरू हो गया है। दरअसल, भारत सरकार की ओर से कृषि सुधारों के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य बिनोद आनंद ने आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों में इसी मंशा को पूरा करने के लिए 'कैंपस कोऑपरेटिव' बनाने का विचार दिया। इसके लिए उन्होंने मंगलौर यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड का उदाहरण दिया जिसका टर्नओवर 2012 में ही करीब 93 लाख रुपये था, जबकि शुद्ध मुनाफा लगभग 20 लाख रुपये था। इसी विचार को अमल में लाने के लिए इस योजना को आगे बढाया जा रहा है।

प्रॉफिट मार्जिन और कॉरपोरेट बिचौलियों को खत्म करके कैंपस सहकारी समितियां छात्रों को कम कीमतों पर खाद्य वस्तुएं, आवास और पाठ्य पुस्तकों जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं।

कैंपस के छात्र-छात्राओं के लिए इस समय व्यापारियों और बिचौलियों के माध्यम से बाजार से सामान आता है और बिकता है। ऐसे में इन सब कामों का इंतजाम कोऑपरेटिव के जरिये करने और उस सप्लाई चेन में किसानों के सीधे जुड़ने से उनके उत्पादों को बेहतर प्लेटफार्म मिल जाएगा। कैंपस कोऑपरेटिव से विद्यार्थियों और किसानों दोनों को फायदा पहुंचेगा। इससे देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। विदेशों में इस पैटर्न पर बहुत से संस्थान काम कर रहे हैं।

कैंपस कोऑपरेटिव बनाने की मुहिम में सहकारिता की शिक्षा देने वाली सबसे बड़ी संस्था वैमनीकॉम में कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट के अलुमनी एसोसिएशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे सहकारी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को उछाल मिलने की उम्मीद है। सहकारी क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए इस समय अवसरों की भरमार है। कैंपस कोऑपरेटिव भविष्य में एक बड़ा प्रोजेक्ट बनकर उभर सकते हैं। इन सहकारी समितियों का विचार हाल के वर्षों में जोर पकड़ रहा है क्योंकि छात्र तेजी से विश्वविद्यालय जीवन के पारंपरिक और कॉरपोरेट संचालित मॉडल के विकल्प तलाश रहे हैं।■

कैंपस सहकारी समितियां कई रूप में काम कर सकती हैं। इनमें खाद्य सहकारी समितियां, पुस्तक भंडार और छात्र सेवा सहकारी समितियां शामिल हैं। खाद्य सहकारी समितियां छात्रों द्वारा संचालित किराना स्टोर या कैफे हैं जो छात्रों को स्वस्थ, स्थानीय रूप से प्राप्त और किफायती खाद्य वस्तुएं प्रदान करते हैं। साथ ही, पोषण और सस्टेनिबिलिटी के बारे में शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं।

गृहिणी जो बनी केक कारोबारी

ग्रीष्मा

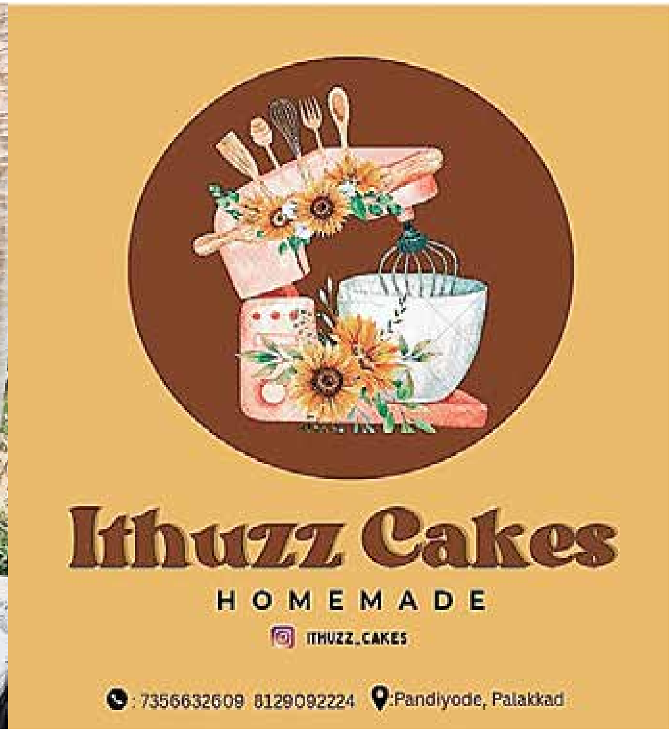

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद से कन्नडी निवासी ग्रीष्मा का सपना हुआ साकार

केक कारोबार शुरू कर बनीं सफल महिला उद्यमी, दूसरों को भी दे रहीं रोजगार

युवा सहकार टीम

केरल की कन्नडी निवासी गृहिणी ग्रीष्मा को हमेशा से बेकिंग का शौक था। उसने अपने जुनून को व्यवसाय में बदलने का सपना देखते हुए केक बनाना सीखा और उसे निखारने में वर्षों बिताए। हालांकि, केक बनाने का कारोबार शुरू करने के लिए आवश्यक उपकरणों और जरूरत की सामग्रियों में निवेश करने के लिए उनके पास वित्तीय साधन नहीं थे। कौशल और दृढ़ संकल्प के बावजूद अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी जुटाने की चुनौती उन्हें भारी लग रही थी।

इस चुनौती से जूझते हुए ग्रीष्मा ने वित्तीय सहायता के लिए नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी (एनवाईसीएस) की कन्नडी शाखा का रुख किया। उनकी क्षमता और वित्तीय सीमाओं को समझते हुए समिति ने उनकी सहायता के लिए समय पर कदम बढ़ाया। एनवाईसीएस के माध्यम से उन्हें गोल्ड लोन मिल गया जिससे उन्हें अपना कारोबार शुरू करने के लिए आवश्यक बेकिंग उपकरण और अन्य बुनियादी चीजें खरीदने के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी मिल गई। यह सहायता उनकी वित्तीय बाधाओं को दूर करने और उनके सपने को हकीकत में बदलने में महत्वपूर्ण था।

वित्तीय सहायता मिलते ही ग्रीष्मा ने घर पर केक बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने अपने दोस्तों, परिवारवालों और आस-पड़ोस के लोगों के लिए केक बनाया। बारीकियों के साथ बनाए गए उनके केक की गुणवत्ता ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। धीरे-धीरे यह बात फैल गई और उन्हें बड़े

ऑर्डर मिलने लगे। जैसे-जैसे मांग बढ़ती गई उनका कारोबार फलता-फूलता गया। इससे उन्हें अपने परिचालन का विस्तार करने और बढ़ते कार्यभार को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए एक छोटी टीम बनाने की जरूरत महसूस हुई।

एनवाईसीएस द्वारा समय पर सहायता के कारण ग्रीष्मा अब एक सफल महिला उद्यमी हैं। उन्हें अब वित्तीय तनाव की चिंता नहीं है। उनका केक कारोबार फल-फूल रहा है। इसकी बदौलत वह न केवल अपने परिवार का आर्थिक रूप से समर्थन कर रही हैं, बल्कि नौकरी के अवसर पैदा करके अपने समुदाय में भी योगदान दे रही हैं। उनकी सफलता की कहानी इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे सही समय पर सही समर्थन महिलाओं को वित्तीय बाधाओं से उबरने और उद्यमशीलता के उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। एनवाईसीएस की सहायता से वह अपने जुनून को एक लाभदायक उद्यम में बदलने, खुशहाल जीवन जीने और दूसरों को अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सक्षम हुई हैं।

हौसलों के आड़े नहीं आई दिव्यांगता

केरल के ही मुंडूर के रहने वाले गिरीश कुमार टी. की सफलता की कहानी भी कम प्रेरणादायक नहीं है। शारीरिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से व्यवसायी बनने का सफर सफलतापूर्वक तय किया। उन्होंने एनवाईसीएस की मुंडूर शाखा से पर्सनल लोन लेकर शुरूआत में एक छोटा व्यवसाय स्पेयर पार्ट्स की दुकान शुरू की जिसका बाद में और विस्तार किया। आज गिरीश पत्नी और दो बच्चों (सभी शारीरिक चुनौतियों के शिकार हैं) के साथ आजीविका के लिए इसी व्यवसाय पर निर्भर हैं।

गिरीश कुमार टी. ने एनवाईसीएस के मुंडूर

गिरीश कुमार टी.

ब्रांच से अपने व्यवसाय के लिए पहले 50 हजार रुपये और फिर 75 हजार रुपये का पर्सनल लोन लिया। लोन की इस राशि का उन्होंने व्यवसाय में बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया और वित्तीय अनुशासन दिखाते हुए समय पर इसका पुनर्भुगतान किया। उनकी दुकान कोंगड मंजेरिकावु में स्थित है। जब उनकी दुकान चल निकली तो उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। चूंकि उन्होंने पहले लिए गए लोन का पुनर्भुगतान समय पर कर रखा था, इसलिए उनकी साख बन गई थी। इस बार उन्होंने 5 लाख रुपये का एक और लोन लेने के लिए आवेदन किया। उनकी प्रतिबद्धता और वित्तीय अनुशासन को देखते हुए मुंडूर ब्रांच ने यह लोन मंजूर कर लिया। इसके लिए उन्होंने अपने नाम की जमीन गिरवी रखी।

इस लोन के माध्यम से वे अपने दुकान का विस्तार करने में सफल रहे। उनकी दुकान उनके और उनके परिवार के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चुनौतियों के बावजूद वह अपनी विश्वसनीयता और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए समय पर ऋण का पुनर्भुगतान कर रहे हैं। सफलता की यह कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने में व्यक्ति के चरित्र की ताकत का प्रमाण है। गिरीश की यह यात्रा आत्मविश्वास की शक्ति और वित्तीय सहायता की उस भूमिका को उजागर करती है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। गिरीश कुमार टी. जैसे लोग सभी को प्रेरित करते हैं।■

चुनौतियों के बावजूद वह अपनी विश्वसनीयता और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए समय पर ऋण का पुनर्भुगतान कर रहे हैं। सफलता की यह कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने में व्यक्ति के चरित्र की ताकत का प्रमाण है।

जैविक खेती से बढ़ेगा रोजगार

'नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन (एनपीओपी)' के आठवें संस्करण का उद्घाटन करते केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एवं अन्य मंत्री।

ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात अगले तीन साल में तीन गुना बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना

दुनिया भर में जैविक उत्पादों की मांग लगभग एक लाख करोड़ रुपये की है, जिसके भविष्य में कई गुना बढ़ने की उम्मीद

ऑर्गेनिक उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि होगी तो उनकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के भी मौके बढ़ेंगे जिससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा

युवा सहकार टीम

जैविक खेती में रोजगार सृजन का नया माध्यम बनने की पूरी क्षमता है। लोगों में खानपान के प्रति जागरूकता बढ़ने से इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। बढ़ती मांग को देखते हुए जैविक उत्पादों को जितना ज्यादा प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और बेहतर पैकेजिंग कर बेचा जाएगा देश-विदेश के बाजारों में उतनी ज्यादा कीमत मिलेगी। इससे रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। जिन किसानों ने जैविक खेती को चुना है उनकी आमदनी बढ़ी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारतीय ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात अगले तीन साल में तीन गुना बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने नई दिल्ली में 'नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन (एनपीओपी)' के आठवें संस्करण में जैविक उत्पाद मानकों में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप एनपीओपी के नए नियम जारी किए।

पीयूष गोयल के मुताबिक, फिलहाल भारतीय जैविक उत्पादों का निर्यात लगभग 5-6 हजार करोड़ रुपये का है जो अगले तीन वर्षों में आसानी से 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। दुनिया भर में जैविक उत्पादों की मांग लगभग एक लाख करोड़ रुपये की है जो आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ सकती है। यह देश के किसानों के लिए बड़ा अवसर है। किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहिए। ऑर्गेनिक उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि होगी तो उनकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के भी मौके बढ़ेंगे जिससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय एक साथ मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया में सबसे अधिक संख्या में ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान भारत में ही हैं। टिकाऊ कृषि पद्धति के रूप में ऑर्गेनिक खेती से पानी की कमी, उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से निपटने में मदद मिलेगी जिसकी वजह मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की पैदावार को नुकसान पहुंच रहा है। ऑर्गेनिक उत्पादन के क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। गोयल ने उम्मीद जताई कि भारत ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्लोबल लीडर के रूप में उभर सकता है। उन्होंने स्टार्टअप्स से ऐसे समाधान निकालने का आह्वान किया जो इस क्षेत्र के विकास में मदद करे।

किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए जैविक उत्पादों की पैकेजिंग और मार्केटिंग पर जोर देते हुए गोयल ने कहा कि यह मूल्य श्रृंखला रोजगार सृजन में भी मदद करेगी और देश एवं दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल करेगी। जैविक क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए उन्होंने अमूल, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल) के प्रयासों की सराहना की। उनके मुताबिक, सहकारी, कृषि और व्यापार क्षेत्र भविष्य में जैविक क्षेत्र को विकसित करने में सहायता करेंगे। इसके लिए बाजार विस्तार और उत्पादों के गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसानों के लिए क्षमता निर्माण और अधिक उपज के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर शोध भी आवश्यक है। अधिक उपज से उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को खरीद निर्णय में मदद मिलेगी।

इस कार्यक्रम में एनपीओपी पोर्टल का अनावरण भी किया गया जो हितधारकों के लिए संचालन को सुगम बनाएगा। पीयूष गोयल ने एनपीओपी के अपग्रेडेड ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म ट्रेसनेट 2.0 को भी लॉन्च किया। ट्रेसनेट 2.0 द्वारा जेनरेटेड पहले पांच रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक ऑपरेटर्स को दिए। इसके अलावा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के हितधारकों के लाभ के लिए उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव और जानकारी के साथ फिर से डिजाइन किए गए एपीडा पोर्टल और एग्री एक्सचेंज पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। यह अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल डेटा विश्लेषण और कृषि निर्यात की रिपोर्ट और डेटा तैयार करने में सक्षम है। वाणिज्य विभाग के अपर सचिव एवं एनपीओपी के चेयरमैन राजेश अग्रवाल के अनुसार, अपग्रेडेड एनपीओपी पोर्टल पारदर्शिता बढ़ाने और किसानों के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एनपीओपी के आठवें संस्करण का उद्देश्य भारत के जैविक खाद्य निर्यात को 2030 तक 2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है।

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के 8वें संस्करण में किसानों सहित हितधारकों के लिए परिचालन को आसान बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख संशोधन पेश किए गए। इसके तहत, जैविक उत्पादक समूहों के लिए प्रमाणन आवश्यकताओं को सरल बनाया गया है। इन समूहों को अब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस) के स्थान पर कानूनी दर्जा दिया गया है। साथ ही, संशोधित छूट प्रावधानों के तहत जैविक खेती में भूमि परिवर्तन की अवधि को तीन साल तक कम करने की संभावना है, जो शर्तों और सुरक्षा उपायों पर निर्भर करती है। इसमें कहा गया है कि जैविक उत्पादक समूहों के आईसीएस को संपूर्ण जैविक उपज की खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए या किसानों को सहायता करने के लिए बाजार संपर्क स्थापित करना चाहिए। सार्वजनिक डोमेन में जैविक किसानों और अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में स्पष्ट जानकारी के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाई गई है जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, निगरानी, सर्विलांस और डेटा एनालिटिक्स के लिए आईटी टूल्स और वेब आधारित ट्रेसिबिलिटी सिस्टम, ट्रेसनेट के एकीकरण के साथ निरीक्षण तंत्र को मजबूत किया गया है।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर एवं मुरलीधर मोहोल और केंद्रीय सहकारिता सचिव सहकारिता डॉ. आशीष कुमार भूटानी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम भारत की जैविक प्रमाणन प्रणाली को मजबूत करने का प्रमुख कार्यक्रम है। यह टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देता है और किसानों एवं निर्यातकों के लिए नए अवसर खोलता है। जैविक उत्पादों के लिए उच्च मानक निर्धारित करके एनपीओपी वैश्विक जैविक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। साथ ही किसानों को पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीके अपनाने में मदद करता है।■

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय एक साथ मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया में सबसे अधिक संख्या में ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान भारत में ही हैं। टिकाऊ कृषि पद्धति के रूप में ऑर्गेनिक खेती से पानी की कमी, उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से निपटने में मदद मिलेगी जिसकी वजह मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की पैदावार को नुकसान पहुंच रहा है।

नौकरी छोड़ जैविक खेती को दे रहे बढ़ावा

युवाओं के लिए बने प्रेरणास्रोत, एग्री स्टार्टअप शुरू कर किसानों के जीवन को रौशन कर रहे पूर्व फुटवियर डिजाइनर

यूट्यूब देखकर जैविक खेती में बढ़ी रूचि, खुद भी खेती करते हैं और किसानों को भी करते हैं प्रोत्साहित

जैविक उर्वरकों सहित कई तरह के कृषि इनपुट का करते हैं उत्पादन, किसानों की उपज की ऑनलाइन मार्केटिंग भी होती है

निशि भट्ट

देश का युवा अब किसानों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। एग्री स्टार्टअप और एग्रीटेक में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है जिसका फायदा किसानों को भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चिनहट के रहने वाले अभिषेक गुप्ता भी ऐसी ही पहल से किसानों के जीवन को रौशन कर रहे हैं। अभिषेक इससे पहले नोएडा की वुडलैंड जूता फैक्ट्री में शू इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। 2022 में उन्होंने नौकरी छोड़कर अनमोल जैविक कृषि उद्यम नाम से एग्री स्टार्टअप शुरू किया। जैविक खेती के महत्व को देखते हुए वे न सिर्फ खुद जैविक खेती करते हैं, बल्कि अन्य किसानों को भी जैविक खेती के बारे में जानकारी देते हैं और इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीके बताने के साथ ही वह अपने उद्यम के माध्यम से अन्य कृषि इनपुट को भी बढ़ावा देने में सहायता कर रहे हैं। अनमोल जैविक कृषि कई तरह के कृषि इनपुट उत्पादों का भी निर्माण करती है जिसकी देशभर में सप्लाई की जाती है।

अभिषेक गुप्ता बताते हैं, 'खेती के प्रति मेरा शुरू से ही लगाव रहा है। मैं चाहता था कि बाहर कहीं जाकर नौकरी करने से अच्छा है कि अपने किसानों के बीच काम किया जाए और उनकी पैदावार बढ़ाने संबंधी जागरूकता बढ़ाई जाए। यही सोचकर मैंने वर्ष 2022 में नौकरी छोड़ दी और लखनऊ वापस आ गया। इसी उद्देश्य से मैंने अनमोल जैविक कृषि उद्यम शुरू किया। यह उद्यम कृषि इनपुट के अन्य उत्पाद भी तैयार कर रहा है।' अभिषेक ने बताया कि किसानों को प्रशिक्षित करने से पहले उन्होंने खुद प्रशिक्षण लिया। वैज्ञानिकों के दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण लेने के बाद अब वह कुछ जैविक कृषि उत्पाद भी बना रहे हैं जो काफी असरदार हैं। जैविक उर्वरक उत्पाद में उनका विशेष काम है

जिसका प्रयोग कर किसान पहले से कहीं अधिक सक्षम हो रहे हैं। ये उर्वरक मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। साथ ही पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। जैविक उर्वरकों के प्रयोग का लाभ पता लगने के बाद किसान इनका अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं।

अभिषेक ने जानवर-रोधी दवा पर भी काम करना शुरू किया है ताकि जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। वे खेती से संबंधित लगभग सभी इनपुट का काम करते हैं जो किसान और खेती संबंधी समस्याओं का निवारण करते हैं। उनके कृषि उत्पाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार सहित कई राज्यों को भेजे जाते हैं। वह कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि वह कृषि इनपुट स्टार्टअप की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाए ताकि अधिक से अधिक किसानों को फायदा हो।

यूट्यूब देखकर जैविक खेती का किया रुख

अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2016 में उन्होंने नोएडा की वुडलैंड कंपनी में सीएडी व सीएएम डिजाइनर के रूप में ज्वॉइन किया था। उनका काम जूतों की डिजाइनिंग का था। उन्होंने एफडीडीआई (फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट) से डिग्री ली है। राजीव दीक्षित के वीडियो देखकर उन्हें जैविक खेती की उपयोगिता के बारे में पता चला। उन्होंने वर्ष 2022 में नौकरी छोड़ दी और लखनऊ आ गए। इसके बाद से पूर्ण रूप से जैविक खेती के काम में लग गए। इसके लिए उन्होंने फर्म का पंजीकरण कराया। अभिषेक का कहना है कि यदि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए और कुछ नया किसानों को बताया जाए तो वह उसे अपनाने के लिए तैयार हैं।

नैचुरल मिशन ऑन नैचुरल फार्मिंग से मिली सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार की नैचुरल मिशन ऑन नैचुरल फार्मिंग योजना के साथ ही कई अन्य योजनाओं की सहायता से किसानों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास रंग ला रहे हैं। हालांकि, जमीनी स्तर पर कई परेशानियां भी देखी गईं। किसान जैविक खेती तो करते थे लेकिन उनकी उपज की उचित कीमत कैसे मिले और उनके उत्पादों की मार्केटिंग कैसे की जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने उत्पादों को सही बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग करना शुरू किया। अब कई राज्यों से अनमोल जैविक उपक्रम के माध्यम से जैविक उत्पादों की मांग की जा रही है। उत्पादों की आपूर्ति में कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प रखा जाता है ताकि किसी भी किसान को गलत तरीके से पैसे का हस्तांतरण न हो सके।■

अभिषेक गुप्ता

किसानों को प्रशिक्षित करने से पहले अभिषेक ने खुद प्रशिक्षण लिया। वैज्ञानिकों के दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण लेने के बाद अब वह कुछ जैविक कृषि उत्पाद भी बना रहे हैं जो काफी असरदार है। जैविक उर्वरक उत्पाद में उनका विशेष काम है जिसका प्रयोग कर किसान पहले से कहीं अधिक सक्षम हो रहे हैं। ये उर्वरक मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हैं।

कोऑपरेटिव बैंकों की बदलेगी बैलेंस शीट

युवा सहकार टीम

कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लगातार प्रयासरत हैं। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए आरबीआई ने अब कोऑपरेटिव बैंकों के लिए बैलेंस शीट और अकाउटिंग के नए प्रारूप का मसौदा जारी किया है। नया प्रारूप आधुनिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और वित्तीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाया गया है। इससे कोऑपरेटिव बैंक भी अब कमर्शियल बैंक की तरह अपनी बैलेंस शीट दुरुस्त रख पाएंगे जिससे गड़बड़ी की कम आशंका रहेगी। कोऑपरेटिव बैंकों के खातों में अक्सर गड़बड़ी की बातें सामने आती रहती है जिससे बैंक के साथ-साथ ग्राहकों का भी नुकसान होता है। आरबीआई का यह कदम कोऑपरेटिव बैंकों को न सिर्फ सशक्त बनाएगा, बल्कि ग्राहकों के हितों की भी रक्षा कर पाने में सक्षम होगा।

आरबीआई ने मसौदा प्रारूप जारी करते हुए इस पर 21 फरवरी, 2025 तक फीडबैक मांगा है। इस प्रारूप (फॉर्म) को जारी करने का मकसद उभरते वित्तीय परिदृश्य और आधुनिक अकाउंटिंग मानकों के साथ तालमेल बिठाना है। आरबीआई ने कहा है कि सहकारी बैंकों के बैलेंस शीट के मौजूदा प्रारूप को पहली बार 1981 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 29 के तहत अधिसूचित किया गया था। तब से अब तक वित्तीय बाजार के साथ-साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस में काफी बदलाव आ चुका है। इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरणों के प्रारूपों की व्यापक समीक्षा की है और बैलेंस शीट और लाभ एवं हानि के संकलन के निदेर्शों के साथ संशोधित फॉर्म और उनके शेड्यूल के प्रारूप जारी किए हैं।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के मुताबिक, सहकारी बैंकों के लिए वित्त वर्ष के अंतिम कार्य दिवस तक अपनी बैलेंस शीट और लाभ एवं हानि का खाता तैयार करना आवश्यक है। कोऑपरेटिव बैंकों, ऑडिटरों और उद्योग विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों से प्रस्तावित परिवर्तन की समीक्षा कर फीडबैक देने को कहा गया है। पोस्ट या ईमेल के माध्यम से आरबीआई के मुंबई मुख्यालय को यह फीडबैक भेजा जा सकता है।

सहकारी बैंकों के सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण पहल

- शहरी सहकारी बैंक अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए अब नई शाखाएं खोल सकेंगे।
- सहकारी बैंक भी वाणिज्यिक बैंकों की तरह दिए गए कर्ज का एकमुश्त निपटान कर सकेंगे।
- ग्रामीण एवं शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत होम लोन की सीमा दोगुनी से अधिक बढ़ाई गई है।
- ग्रामीण सहकारी बैंक अब कमर्शियल एवं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट क्षेत्र को कर्ज दे सकेंगे ताकि उनका कारोबार विविधिकरण हो सके।
- शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने दी अनुमति।
- सभी सहकारी बैंकों को सीजीटीएमएसई योजना में बतौर सदस्य ऋणदाता संस्थान के रूप में पात्र बनाया गया है।
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक शीर्ष संगठन की स्थापना की गई है।

NANO TECHNOLOGY
NANO UREA & DAP
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
IFFCO KISAN DRONE
असरदार जोड़ी
नैनो यूरिया प्लस
सागरिका
नैनो डी ए पी
IFFCO
NANO UREA PLUS
IFFCO
सागरिका
SAGARIKA
100% प्राकृतिक समुद्री उत्पाद
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO DAP
(8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017, भारत
फोन नंबर- 91-11-26510001, 91-11-42592626, वेबसाइट www.iffco.coop
इफको नैनो उर्वरकों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया स्कैन करें"

शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTRY OF EDUCATION
GOVERNMENT OF INDIA

nbt.india

Knowledge Partner of the Nation

नई दिल्ली
विश्व पुस्तक मेला

1-9 फरवरी 2025

हॉल संख्या 2-6, भारत मंडपम

थीम

गणतंत्र@75 - भारत के 75वें गणतंत्र दिवस का उत्सव (1950-2025)

हम, भारत के लोग...

We, the People of India...

20+ लाख पाठक

50+ देश

5000+ प्रकाशक

2000+ स्टॉल्स

600+ कार्यक्रम

मुख्य आकर्षण

बाल फिल्म महोत्सव • लेखक लाउंज • इलस्ट्रेटर कॉर्नर • डिजिटल अनुभव क्षेत्र

CEOSpeak a forum for publishing	New Delhi Rights Table	Festival of Festivals	Children's Pavilion	Authors' Corner	Cultural Programs
2 फरवरी 2025	3-4 फरवरी 2025	1-9 फरवरी 2025	1-9 फरवरी 2025	1-9 फरवरी 2025	1-9 फरवरी 2025

शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTRY OF EDUCATION
Government of India

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025

1-9 फरवरी 2025 • भारत मंडपम, नई दिल्ली

nbt.india

आई टी पी ओ ITPO

प्रिय पाठक................................,

हम आपको **नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025** के उद्घाटन समारोह के साथ-साथ दिनांक **1-9 फरवरी 2025** तक आयोजित पुस्तक मेले व अन्य कार्यक्रमों में सपरिवार सादर आमंत्रित करते हैं। किताबों की बहुभाषी दुनिया में आपका स्वागत है।

युवराज मलिक
निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत

उद्घाटन समारोह: 1 फरवरी 2025

पुस्तक मेला व अन्य कार्यक्रम : 1-9 फरवरी 2025

कृपया इस आमंत्रण पत्र की मूल प्रति पर अपना नाम लिखकर ndwbf4women@gmail.com पर भेजें और निःशुल्क प्रवेश के लिए अपना ई-पास* प्राप्त करें।

*एक ई-पास अधिकतम चार सदस्यों के लिए मान्य।

RSVP: ndwbf4women@gmail.com